This amount has since been recovered from the party.

**शहरी गरीबों को सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराने की योजना**

792. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या नागरिक आपूर्ति,उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कुल कितने प्रकार की सार्वजनिक वितरण प्रणालियां काम कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार शहरी गरीबों को ग्रामीण गरीबों की अपेक्षा सस्ती दरों पर राशन देने की कोई योजना बना रही हैं;

(ग) इस समय खाद्य सब्सिडी पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जाती हैं और इस योजना से इसके लिए कितनी अतिरिक्त सब्सिडी ककी आवश्यकता होगी; और

(घ) इस संबंध में ब्यौरा क्या हैं ?

**नागरिक पूर्ति,उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** (**श्री बूटा सिंह** ): (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली सारे देश में लागू हैं । केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न क्षेत्र विकास कार्यक्रमों,जैसे मरूस्थल विकास कार्यक्रम,सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम,निर्धारित पहाड़ी क्षेत्रों तथा समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं के तहत आने वले ब्लाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पहुंच में सुधार करने के लिए 1992 में संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की थीं ।

(ख) जी,नहीं ।

(ग) और (घ) गत तीन वर्षो के दौरान खाद्य राजसहायता के खाते में निर्मुक्त राशियां तथा 1995-96 बजट अनुमान इस प्रकार हैं :-

| वर्ष | करोड़ रूपए में |
|---|---|
| 1992-93 | 2785 |
| 1993-94 | 5537 |
| 1994-95 | 4509 |
| 1995-96 (बजट अनुमान) | 5252 |

चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों की तुलना में शहरों में रहने वाले गरीब लोगों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न वितरण करने की कोई स्कीम नहीं हैं अत: ऐसी किसी स्कीम पर कोई अतिरिक्त राजसहायता खर्च किए जाने का प्रश्न नहीं उठता हैं ।

**Guidelines for consultancy business**

793. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(c) Export of consultancy services, including computer software, in terms of foreign exchange earnings, during 1994-95 was estimated Rs. 1700 crore (Source. FIEO), which marked a growth rate of 24% over the previous year.

(a) whether it is a fact that Government have formulated new guidelines to promote foreign consultancy at the cost of Indian consultancy business;

(b) if so, what steps Government propose to take to remove such guidelines; and

(c) what are the details of the growth rate of Indian consultancy business during the year 1994-95?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI Pi CHIDAMBARAM): (a) No, Sir.

(b) Docs not arise.

**Scam in coal sector**

794. SHRI PRAMOD MAHAJAN:
SHRI VIREN J. SHAH:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a report published in the 'Indian Express' of Ist May, 1995 under the caption, "Scam in PSUs puts Bofers to shame";